20
अध्याय

ई–गवर्नेंस एवं टेलीमेडिसिन

20-1 b&xoul lc/kh igy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की कार्य–कुशलता तथा प्रभावकारिता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न ई–गवर्नेंस/ई–हैल्थ (आईसीटी का प्रयोग) को अंगीकार करने की पहल की है। आने वाले वर्षों में मंत्रालय विभिन्न उत्तरोत्तर योजनाओं व नई पहल को लागू कर रहा है। विभिन्न पहलों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया गया है जिनमें नागरिक केन्द्रित सेवाएं, सूचना प्रबंधन प्रणाली, मानकीकरण (अंगीकरण व प्रोत्साहन), विनियम इत्यादि शामिल हैं।

20-1-1 ixfr o miyfC/k;k

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न गतिविधियां/कार्य किए ताकि केन्द्र और राज्य स्तर पर एकीकृत रीति से ई–हैल्थ का कार्यान्वयन हो पाए। ये गतिविधियां/कार्य नीचे दर्शाए गए हैः

d- jk"Vh; LokLF; ikVy ¼,u,pih½

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल 14 नवम्बर, 2014 को शुरू किया गया था जो नागरिकों, छात्रों, स्वास्थ्य परिचर्या व्यावयियों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रमाणिक स्वास्थ्य सूचना हेतु एकल पहुँच बिन्दु है। (http://www.nhp.gov.in)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, नई दिल्ली में कई नए व मूल्य–वर्धक पक्ष जोड़े गए। ऐसी की मुख्य विशेषताओं में निम्न

शामिल हैः

i. ,u,pih ok;l iksVZy% टॉल फ्री राष्ट्रीय नं. 1800–180–1104 के माध्यम से स्वास्थ्य, रोग, रहन–सहन, प्राथमिक सहायता, निर्देशिका सेवाएं, स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। मौजूदा समय में एनएचपी वॉयस पोर्टल पर हिन्दी, गुजराती, बांग्ला, तमिल तथा अंग्रेजी में स्वास्थ्य सूचना दी जा रही है।

ii. ,u,pih dh fy, ekckby ,Iyhds'ku% मोबाइल फोन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल तक पहुँच बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है ताकि एनएचपी निर्देशिका सेवा अर्थात् राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) सहयोगी रक्त बैंक, अस्पतालों की अवस्थिति आदि जानी जा सके।

iii. vUrjjk"Vªh; ;ksx fnol ¼vkbZMhokbZ½ iksVZy% अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस (21.06.2015) हेतु एनएचपी आयुष मंत्रालय का का आधिकारिक पोर्टल था। आईडीवाई के दौरान 10,000 से ज्यादा वीडियो तथा इमेज अपलोड किए गए थे।

[k- vkWu&ykbu iathdj.k iz.kkyh ¼vksvkj,l½

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में ओआरएस की शुरूआत की गई थी यह प्रणाली विभिन्न अस्पतालों को लिंक करते हुए ऑन लाइन पंजीकरण, शुल्क की अदायगी तथा अपॉइंटमेंट तथा ऑन लाइन नैदानिक रिपोर्ट, रक्त उपलब्धता की ऑन लाइन जानकारी इत्यादि हासिल करने का माध्यम है।

- आज की तारीख तक, एम्स, नई दिल्ली, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्पोर्ड्स इंजरी केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल, निम्हांस, अगरतला, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिपमेर जैसे 14 बड़े अस्पताल ओआरएस प्रणाली से जुड़ें हैं और अभी तक कुल 140 विभाग लिंक किए जा चुके हैं और 1,00,000 से अधिक अपॉइंटमेंट ली गई हैं।

- मंत्रालय और अधिक अस्पतालों को ओआरएस पर लिंक करने के लिए कई प्रयास कर रहा हैं।

x- LokLF; lqfo/kkvksa dh fy, jk"Vªh; igpku la[;k ¼,uvkbZ,u½

- विभिन्न डाटा बेस में कोई कॉमन पहचान न होने के कारण स्वास्थ्य सूचना व रोगी रिकॉर्ड विभिन्न आईटी प्रणालियों में ही उलझा रहता है इस चुनौती से निपटने के लिए (वास्तव में कोई अन्तर प्रचालन नहीं) विस्तृत चर्चा और परामर्श के उपरांत मंत्रालय ने प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र (सरकारी एवं निजी) को एक अलग अनूठी संख्या अर्थात एनआईएन आबंटित करने का निर्णय लिया ताकि विभिन्न स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों में सूचना आदान–प्रदान तथा अन्तर प्रचालन संभव हो पाए। यह नागरिको के इलैट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के बारे में भी

सचेत है। एनआईएन डाईट वाई के मेटाडाटा मानकों (एमडीडीएस) का अनुपालन करेगा। गोवा राज्य में एनआईएन सृजित करने और इसके सत्यापन का पायलेट फेस पूरा किया जा चुका है। एनआईएन के लिए वेब एप्लीकेशन विकसित की जा चुकी है।

?k- ,dhd`r LokLF; lwpuk IysVQkeZ ¼vkbZ,pvkbZih½

- अन्तर प्रचालन सुविधा की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा/स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सृजन के आदान–प्रदान, नागरिक सेवाओं इत्यादि के लिए मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म आईएचआईपी) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

- परिणामों के सेट की उपलब्धि के लिए सार्वजनिक और निजी सहित विभिन्न पणधारकों के सहयोग से आईएचआईपी की स्थापना की जाएगी। इसमें क्लाउड सहित नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां शामिल की जाएगी।

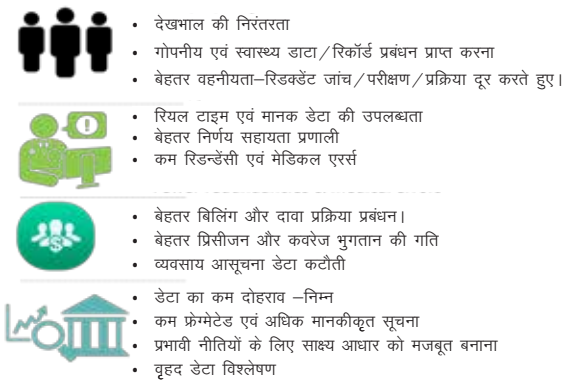

- पणधारकों, डाइट वाई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से इस संबंध में एक कन्सेप्ट नोट तैयार किया जा रहा है।

M- byDVªkfud LokLF; fjdkMZ ¼bZ,pvkj½

- मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2013 में ईएचआर मानकों को अधिसूचित किया गया। उसके बाद भारत 1 अप्रैल, 2014 से अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य टर्मिनोलोजी मानक विकास संगठन (आईएचटीएसडीओ), डेनमार्क का सदस्य राष्ट्र बन गया जिसके पास एसएनओएमईडी–सीटी अर्थात् मेडिसीन ऑफ सिस्टेमेटाईज्ड नोमेनक्लेचर–क्लीनिकल अर्म्स, ईएचआर के लिए अधिसूचित मानकों में से एक के प्रदाय का अधिकार है।

ihtsdo अग्रणी स्वास्थ्य चिकित्सा टर्मिनलोजी विश्वव्यापी

- भारत के सभी वेंडर और स्वास्थ्य पेशेवर आईएचटीएसडीओ को किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए बिना भारत में प्रयोग होने वाले ईएचआर एप्लिकेशन के लिए एसएनओएमईडी–सीटी का प्रयोग कर सकता है। मंत्रालय ने अप्रैल, 2014 में आईएचटीएसडीओ से राष्ट्र सदस्यता प्राप्त कर ली है और इसका नवीकरण कर लिया है।
- देश में एसएनएमईडीओ–सीटी का प्रयोग बढ़ाने तथा संबंधित कार्यकलाप के लिए सम्पर्क के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रालय ने नेशनल रिलीज सेंटर (एनआरसी) के रूप में विकसित गणना विकास केन्द्र (सीडीएसी) को नामित किया है। अभी तक भारत में एसएनओएमईडी–सीटी के प्रयोग के लिए 80 से अधिक संबद्ध लाइसेंसो को अनुमोदित किया गया है।

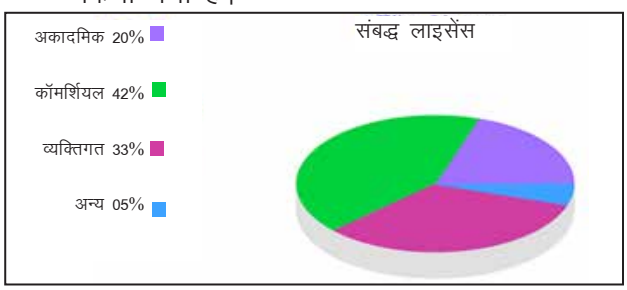

- नेशनल रिलीज सेंटर के लिए वेबसाइट http://snomedctnrc.in शुरू किया गया है जो एसएनओएमईडी–सीटी सहायता और प्रयोग के लिए एक वन स्टॉप विंडो है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी–डीएसी, आईएचटीएसडीओ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, एफएक्यू आधारित यूजर क्वेरी और कार्यान्वयन में एसएनओएमईडी–सीटी का प्रयोग, भारत में एसएनओएमईडी सीटी से संबंधित समाचार और घटनाएं आदि पर वेबसाइट और उसे संबद्ध खंडों में लिंक का प्रावधान है। इसमें विगत कार्यशालाओं/प्रशिक्षण के उपलब्ध सामग्री, एसएनओएमईडी सीटी कार्यान्वयन दिशा–निर्देश आदि का भी प्रावधान है।

- कुछ रोगों की श्रेणियों हेतु संदर्भ सेटों के विकास के लिए कार्यों का सृजन किया गया है जिसके संदर्भ सेटों के प्रकाशन के लिए सदस्य नेमस्पेस प्राप्त करने के लिए आईएचटीएसडीओ के साथ पत्राचार करके अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए संदर्भ सेटों को जारी किया जाएगा।
- मंत्रालय और एनआरसी के अधिकारियों ने अक्तूबर, 2015 में उरूग्वे में आयोजित सदस्य फोरम की व्यवसाय बैठकों और एडवाइजरी समूहों में भाग लिया। क्लिनिशियन और सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर वेंडरों के बीच एसएनओसीएमईडी सीटी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरू सहित देशभर में कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से प्रतिनिधियों सहित लगभग 772 लोगों को पंजीकृत किया गया और कार्यषालाओं में 438 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। हाल ही में, एनआरसी ने फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में विशेषतः बीमा समुदाय के लिए एसएनओएमईडी सीटी के आरंभ और प्रयोग पर एक मास्टर कक्षा का आयोजन किया।

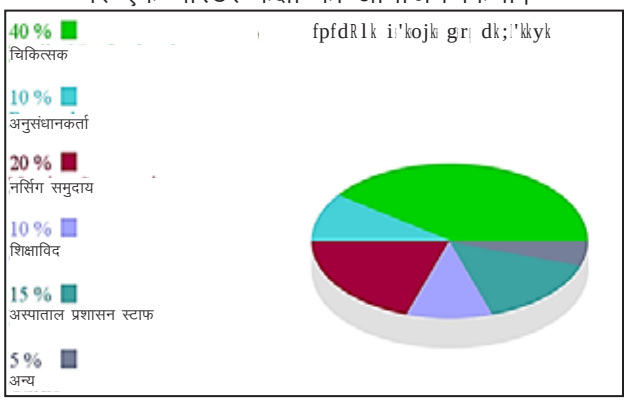

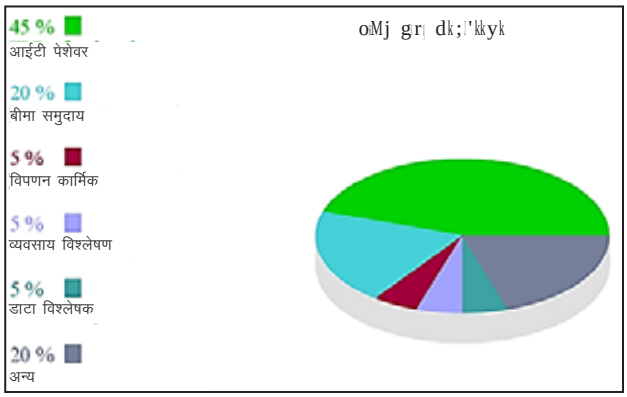

- ई–शिक्षण कोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसएनओएमईडी सीटी के लिए टूल किट का विकास किया गया है और निःशुल्क उपलब्ध है। टूल किट में स्वास्थ्य चिकित्सा अनुप्रयोग में एसएनओएमईडी सीटी के सरल और तीव्र एकीकरण के लिए एपीआई और सॉफ्टवेयर टूल शामिल है। एसएनओएमईडी सीटी के प्रभावी कार्यान्वयन के भाग के रूप में विभिन्न संगठनों/वेंडरों को टूल किटों पर प्रशिक्षण और सहायता प्रदान किया गया है। एसएनओएमईडी सीटी से आईसीडी 10 मैपिंग टूल के सृजन पर कार्य आरंभ की गयी है।
- राष्ट्रीय और वैश्विक तौर पर समकालीन विकास के

तर्ज पर ईएचआर मानकों के उन्नयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया है तथा यथाअपेक्षित मानकों का संषोधन करने के अधिदेश के साथ कार्य कर रहा है।

p- jk"Vh; b&gYFk ikf/kdj.k ¼,ubl,p,½

- राष्ट्रीय ई–हेल्थ मानकों को बढ़ावा देने, अपनाने तथा विनियमन के लिए तथा ई–हेल्थ में कार्यनीतिक पहलों के लिए एक नोडल राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय ई–हेल्थ प्राधिकरण का गठन किए जाने की परिकल्पना की गई है। विधायिका (संसद के अधिनियम) के माध्यम से इसका गठन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिसके निम्नलिखित विजन/लक्ष्य होंगेः–

क) देश के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में ई–हेल्थ मानकों और ई–हेल्थ सोल्यूशन के अंगीकरण और विनियमन का इस प्रकार से मार्गदर्शन करना ताकि किफायती लागत तरीके से विभिन्न स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा का भंडारण/आदान–प्रदान और स्वास्थ्य और गवर्नेंस डेटा का सार्थक एकीकरण हो सके।

ख) स्वास्थ्य सूचना आदान–प्रदान के माध्यम से बहु स्वास्थ्य आईटी प्रणालियों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना।

ग) राज्य स्तरीय तथा देश व्यापी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भण्डार/आदान–प्रदान प्रणाली के नियमित विकास का निरीक्षण करना जो सुनिश्चित करे कि रोगी को डेटा का संरक्षा, गोपनीयता और निजता का रखरखाव हो तथा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित हो।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा अनुमोदित एनईएचए के गठन पर एक कंसेप्ट नोट सार्वजनिक डोमेन में रखा गया जिसमें माईगॉव (Mygov) प्लेटफार्म शामिल है तथा 10 मई, 2015 तक टिप्णियां और सुझाव आमंत्रित किया गया है। कंसेप्ट को अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सुझाव/टिप्पणियों के लिए परिचालित भी कर दिया गया है। प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर कंसेप्ट नोट का संशोधन किया जा रहा है।

N- byDVkfud LokLF; MVk dh futrk vkj lj{kk

- सूचना/डेटा की निजता और सुरक्षा एक मुख्य मुद्‌दा है जिसे ई–हेल्थ में दूर किया जाना है। साझेदारी, सुगमता एवं सुरक्षित ईएचआर का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए सूचना की साझेदारी के लिए उचित विधिक रूपरेखा का विकास करने की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है।

- मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा निजता एवं सुरक्षा के लिए विधायिका के साथ जाने का निर्णय लिया है। तदनुसार विधायिका तैयार करने का कार्य चल रहा है।

t- vU;

- Hkkjrh; ljdkjh oclkbV d fy, fn'kkfun'k ¼thvkbthMCY;½ के अनुरूप मंत्रालय की वेबसाइट बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

- dk;ky; dk vkVke'ku& ई–ऑफिस प्रोडक्ट (एनआईसी द्वारा) जिसका उद्देश्य अधिक सक्षम और पारदर्शी अंतर और अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में प्रवेश कर गवर्नेंस की सहायता करना है, का

कार्यान्वयन किया जा रहा है। ई–ऑफिस में सभी सरकारी कार्यालयों के सरल, सक्षम और पारदर्शी काम–काज की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, सूचना प्रबंधन प्रणाली, नियोक्ता मास्टर विवरण, वेतन पर्ची, अवकाश प्रबंधन प्रणाली, संदेश, साझा दस्तावेज और महत्वपूर्ण फार्म को अपलोड करने जैसे माड्यूल प्रयोग में हैं। ई–दौरा, विधिक मामले, स्थापना फाईलों के कार्यान्वयन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- Hkkjrh; vrjk"Vh; 0;kikj eyk ¼vkbvkbVh,Q½] 2015 e Hkkxhnkjh–मंत्रालय के ई–गवर्नेंस प्रभाग (http://www.nhp.gov.in/media/health-pavallion-iitf-2015) द्वारा आईआईटीएफ में हेल्थ पैविलियन का आयोजन किया गया।

स्वास्थ्य पैविलियन, आईआईटीएफ 2015 में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा

- Hkkjrh; vrjk"Vh; foKku mRlo ¼vkbvkbl,l,Q½] 2015 e Hkkxhnkjh&स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में 04 से 08 दिसम्बर 2015 के दौरान आईआईएसएफ, 2015 में भाग लिया तथा मंत्रालय की विभिन्न ई–गवर्नेंस पहलों का प्रदर्शन किया गया।

20-2 b&LokLF; ¼VyhefMflu½

20-2-1 Hkkjr e VyhefMflu dk Øfed fodkl% lf{kIr lkj

- वर्ष 2005 में टेलीमेडिसिन संबंधी कार्य–बल का गठन किया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने टेलीमेडिसिन सहित ई–स्वास्थ्य के लिए बजट अनुमोदित किया था।
- 2007 में, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ स्थित स्कूल ऑफ टेलीमेडिसिन एंड बायो–इंफार्मेटिक्स को डीईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन और जैव चिकित्सीय इंफोर्मेटिक्स संसाधन केंद्र बना दिया गया था।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के अनेक भागों में टेली–ऑप्थैल्मोलॉजी ऑनको–एनईटी प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान की।
- अनेक राज्यों ने टेलीमेडिसिन में आईसीटी की विभिन्न पहलें शुरू की हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। ओडिशा, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान और कर्नाटक ने टेलीमेडिशन के क्षेत्र में प्रायोगिक योजनाएं आरंभ की हैं।

20-2-2 LokLF; vkj ifjokj dY;k.k e=ky; }kjk 'kq: dh xb VyhefMflu lc/kh igy

d- ,u,elh,u ifj;ktuk dh LFkkiuk

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएमसीएन को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें ई–शिक्षा और ई–स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी के प्रयोजन के साथ एनकेएन (राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क–हाई स्पीड बैंडविद कनेक्टिविटी) के दौरान पहले चरण में 41 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है;
- 103.99 करोड़ की धनराशि वाली इस स्कीम को फरवरी, 2014 में अनुमोदित किया गया था और इस स्कीम के चरण–1 के अंतर्गत टेली–शिक्षा, टेली–सीएमई, टेली–विशेषज्ञ परामर्श, टेली अनुवर्ती कार्रवाई और डिजिटल पुस्तकालय की उपलब्धता आदि के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (एसजीपीजीआई, लखनऊ) एवं पांच क्षेत्रीय संसाधन केंद्र, (एम्स, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, जिपमेर, पुदुच्चेरी और निग्रिम्स, शिलांग और केईएम,

मुंबई में), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) द्वारा प्रदान की गई कनेक्टिविटी वाले 35 अन्य चिकित्सा कॉलेजों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा;

- शेष चिकित्सा कॉलेजों को आगामी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार अगले चरण में लिया जाएगा;
- एनएमसीएन के प्रचालन के लिए दिशा निर्देश और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गई हैं;
- राज्य सरकारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे है।
- एनएमसीएन के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) और वित्तीय मूल्यांकन समिति (एफईसी) गठित की गई है; और
- प्रणाली समकलक (एसआई) का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है।

20-2-3 ubl igy

d- LokLF; {k= e vrfj{k ik|kfxdh dk mi;kx

माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ''गवर्नेंस और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना'' विषय पर राष्ट्रीय बैठक की आगामी कार्रवाई पर चर्चा का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अय्यपन टेम्पल (पम्पा) एवं हिमाचल प्रदेश में टेलीमेडिसिन नोड की स्थापना द्वारा अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से नागरिक आधारित टेली हेल्थ केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन पायलेट परियोजनाओं की संकल्पना की है।

or|eku fLFkfr

- पम्पा, अय्यपन टेम्पल में टेलीमेडिसिन नोड को अंतरिक्ष विभाग से सेटकॉम कंनेक्टिविटी के साथ प्रचालनशील बनाया गया।
- टेली हेल्थ सर्विस सेवाएं प्रदान करने के लिए पीजीआई, चंडीगढ़ के साथ जोड़ने के लिए टेलीमेडिसिन नोड की स्थापना करने हेतु सीएचएस, पूह का चयन किया गया है।

[k- rEckdw fu"k/k dh fy, ,e &LokLF;

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विष्व स्वास्थ्य संगठन की भागीदारी में भारत में तम्बाकू निषेध के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की संकल्पना की है। डब्ल्यूएचओ के *''बी हेल्थी बी मोबाइल''* पहल के भाग के रूप में सभी श्रेणियों के उन तम्बाकू प्रयोगकर्ताओं तक पहुँचने जो तम्बाकू का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं तथा सतत संदेश के माध्यम से सफलतापूर्वक तम्बाकू छोड़ने में उन्हें सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है।

or|eku fLFkfr

- तम्बाकू निषेध के लिए एसएमएस आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएचओ–आईटीयू के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है।
- संदर्भ विषय को भारत की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार रूचिकर बनाया गया है तथा इसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, और
- प्रभाग ने दिसम्बर, 2015 तक अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है।

20-2-4 vkxkeh foRrh; o"k ¼2016&17½ e fu;kftr dk;ldyki

- 41 चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में एनएमसीएन के प्रथम चरण का कार्यान्वयन;
- अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से चारधाम, कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ तीर्थ स्थल में टेलीमेडिसिन नोड की स्थापना;
- अंतरिक्ष विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता से जिओ–वेब पोर्टल का डिजाइन और विकास; और
- क्षेत्रीय भाषाओं में एम–हेल्थ पहल की शुरूआत।

20.2.5 वर्तमान वित्तीय वर्ष (2015-16) के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत टेलीमेडिसिन के लिए, राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

वित्तीय वर्ष 2015–16 में तीन राज्यों को निम्नानुसार 498.62 लाख रू. आबंटित किए गए थे (आरओपी के अनुसार)

- हिमाचल प्रदेश : 37.50 लाख रू.
- महाराष्ट्र : 216.40 लाख रू.
- त्रिपुरा : 244.72 लाख रू.